श्री रंगा निलयम राम कृष्ण राव

बनाम

कंदोकोरी चेल्लायम्मा उर्फ मंगम्मा और एक अन्य

[सैय्यद फजल अली, मुखर्जी एवं चन्द्रशेखर अय्यर न्यायाधिपति]

मद्रास कृषक राहत अधिनियम (1938 का IV), एस.एस. 3 (घ), 8, 10, 19-- डिक्री निष्पादन में संपत्ति की बिक्री --क्या मालिक "कृषक" नहीं रहेगा बिक्री को रद्द करने के लिए आवेदन लम्बित होने तक -बिक्री को रद्द करने के लिए आवेदन और अधिनियम के तहत राहत के लिए-पोषणीयता-आदेश पुष्टिकरण बिक्री और राहत देना--वैधता--सीपीसी (1908), आदेश XXI, नियम 90--निष्पादन विक्रय-- अपास्त करने से इंकार करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील एक तरफ बिक्री--बिक्री पूर्ण हो जाती है और स्वामित्व पारित हो जाता है- रिसीवर-रिसीवर की नियुक्ति, का प्रभाव।

एक बंधक पर प्राप्त डिक्री के निष्पादन में, बंधककर्ता के स्वामित्व वाला एक गाँव जो बंधक में शामिल था, अदालत द्वारा 6 जुलाई 1935 को बेच दिया गया था और इसे बंधकदार द्वारा खरीदा गया था। आदेश XXI, नियम 90 सी.पी.सी के तहत बंधककर्ता द्वारा अनियमितताओं के लिए बिक्री को अपास्त करने के लिए एक आवेदन को खारिज कर दिया गया था, बिक्री की पुष्टि की गई थी और 6 मार्च 1943 को डिक्री की पूरी संतुष्टि को फिर से लागू किया गया था। कुछ दिनों के बाद बंधककर्ता और उनके

गोद लिए हुए बेटे ने अधिनियम के तहत राहत के लिए प्रार्थना करते हुए धारा 19 मद्रास कृषि राहत अधिनियम, 1938 के तहत एक आवेदन किया,, और चूंकि यह आवेदन भी खारिज कर दिया गया था, उन्होंने दो अपीलों को प्राथमिकता दी, एक इस आवेदन को खारिज करने वाले आदेश से और दूसरी 6 मार्च 1943 के आदेश के खिलाफ बिक्री को अपास्त करने से इनकार करते हुए। मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि चूंकि बंधककर्ता का गाँव बेच दिया गया था, इसलिए वह मद्रास कृषि राहत अधिनियम की धारा 3 के परंतुक के खंड (घ) के दायरे में नहीं आता था और इसलिए वह अधिनियम के तहत राहत का दावा करने का हकदार था और अधिनियम के प्रावधानों के तहत ऋण का भुगतान किया गया था, लेकिन बिक्री अपास्त करने के लिए उत्तरदायी नहीं थी; और इस निर्णय अनुसार डिक्री-धारक को उस राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था जिसके लिए संपत्ति को उस पर ब्याज के साथ बेचा गया था

फजल अली और मुखर्जी जे के अनुसार अभिनिर्धारित- (i) कि उच्च न्यायालय द्वारा जो निष्कर्ष दिये गये वे आत्म-विरोधाभासी थे क्योंकि यदि बिक्री उस तारीख को प्रभावी थी जिस दिन यह आयोजित की गई थी या पुष्टि की गई, डिक्री भी उस तिथि पर संतुष्ट थी और निर्णय-देनदार अब अधिनियम के प्रावधान लागू करने के हकदार नहीं थे (ii) कि उच्च न्यायालय इस आधार पर अपील का निर्णय करने में कानूनी रूप से उचित

नहीं था कि निर्णय-देनदार बिक्री की तारीख से गाँव के मालिक नहीं रहे और उस कारण से अधिनियम की धारा 3 के परंतुक के खंड (घ) द्वारा प्रभावित नहीं हुए। जब किसी आवेदन को अस्वीकार करने वाले आदेश से, आदेश XXI, नियम 90 सी. पी. सी के तहत अपील की जाती है निष्पादन बिक्री को अपास्त करने के लिए, बिक्री तब तक निरपेक्ष नहीं हो जाती जब तक कि मामला अपीलीय न्यायालय द्वारा अंततः निर्णित हो जाए।

चंद्रसेखर अय्यर जे के अनुसार:1935 में बिक्री के बाद, गांव में निर्णय-देनदारों का एकमात्र हित यह था कि सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत बिक्री को रद्द कर दिया जाए। यह हित अधिनियम की धारा 3, उप-खंड (ii) (क) & (ख) व धारा 19(1) द्वारा अपेक्षित हित नहीं है; अधिनियम के अनुसार, वे "कृषक" नहीं थे और किसी भी अधिकार के हकदार नहीं थे।

फजल अली और मुखर्जी जे के अनुसार भी अभिनिर्धारित: एक व्यक्ति अधिनियम की धारा 3 के परंतुक के खंड (घ) के तहत केवल इसलिए किसी संपत्ति भूमि-धारक होना बंद नहीं होता है क्योंकि संपत्ति को रिसीवर के हाथों में सौंप दिया गया है।

भवानी कुंवर बनाम मथुरा प्रसाद सिंह (आई. एल. आर. 40 कैल. 89)और चंद्रमणि शाह बनाम अनारजन बीबी (आई. एल. आर. 61 कैल. 945) संदर्भित किया गया।

मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया गया।

अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1949 की सिविल अपील संख्या 56 और 57। 1943 की ए.ए.ओ. संख्या 372 और 1944 की 634 में मद्रास उच्च न्यायालय (वड्सवर्थ और पतंजलि शास्त्री जेजे) के 24 अक्टूबर, 1945 के आदेशों के खिलाफ अपील जो एलोर के अधीनस्थ न्यायाधीश के आदेशों 1937 के ई.ए. नंबर 440 में और 1923 के ओ.एस. नंबर 87 में 1943 के सीएमपी नंबर 152 के खिलाफ अपीलें थीं।

अपीलकर्ता की ओर से पी. सोमसुंदरम (वीवी चौधरी, उनके साथ)।

प्रत्यर्थियों के लिए वी. रंगाचारी (के. मंगाचारी, उनके साथ)।

1950. अक्टूबर 17 । न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय सुनाया।

फ़ज़ल अली जे.-ये अपीलें निष्पादन कार्यवाही से उत्पन्न होती हैं, और उनमें तय किया जाने वाला मुख्य बिंदु यह है कि मद्रास कृषक राहत अधिनियम (1938 का मद्रास अधिनियम IV, जो कि इसके बाद "मद्रास अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के कुछ प्रावधानों का पक्षकारों के अधिकारों पर क्या प्रभाव होगा। यह बिन्दु किस तरह उत्पन्न होता है मामले के तथ्यों के संक्षिप्त विवरण से स्पष्ट हो जाएगा।

ऐसा प्रतीत होता है कि 1908 में, प्रथम प्रत्यर्थी के पति, वीरेशलिंगम ने 9,000 रुपये की राशि सीतारमय्या नाम के एक व्यक्ति से उधार ली थी और उसके पक्ष में एक बंधक बॉन्ड निष्पादित किया। इसके बाद बंधकदार

द्वारा बंधक को लागू करने के लिए एक मुकदमा दायर किया गया और उस मुकदमे में एक अंतिम डिक्री 19 अगस्त, 1926 को पारित की गई। इसके बाद, 28 अक्टूबर, 1931 को, डिक्री-धारक ने गिरवी रखी गई संपत्ति की बिक्री द्वारा डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन किया। 1933 में, डिक्री-धारक ने डिक्री को सोभनाद्री को हस्तांतरित कर दिया, जिसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे, हमारे सामने अपीलकर्ता, को निष्पादन कार्यवाही में उनके कानूनी प्रतिनिधि के रूप में अभिलेख पर लाया गया था। डिक्री के समनुदेशन से कई साल पहले, प्रतिवादी, वीरेशलिंगम की मृत्यु हो गई थी और इसलिए उसकी विधवा, पहली प्रतिवादी, को कानूनी प्रतिनिधि के रूप में अभिलेख पर लाया गया। 6 जुलाई, 1935 को, डिक्री के निष्पादन में संपत्ति की दो वस्तुएं बेची गईं और डिक्री धारक द्वारा खरीदी गईं, ये थीं:--- (1) पश्चिम गोदावरी जिले में टेडलाम नामक एक गांव; और (2) मेडपल्ली गांव में 4 एकड़ और 64 सेंट भूमि। पहली संपत्ति 21,000 रुपये में बेची गई थी और दूसरी 1,025 रुपये के लिए। हालाँकि, डिक्री के तहत देय राशि केवल लगभग रु 17,860 थीं, दूसरी संपत्ति की बिक्री को बाद में रद्द कर दिया गया और डिक्री-धारक ने डिक्रीटल राशि को संपत्ति की पहली वस्तु की कीमत के विरुद्ध मुजरा करने के बाद लगभग रु.3000 की अतिरिक्त राशि अदालत में जमा कर दी। 5 अगस्त, 1935 को, पहले प्रत्यर्थी ने जुलाई, 1935 में हुई बिक्री को रद्द करने के लिए आदेश XXI, नियम 90 और नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 47 के तहत एक आवेदन दायर

किया, जिसमें बिक्री के संचालन में कुछ अनियमितताओं का आरोप लगाया गया। वह आवेदन कई वर्षों के बाद एलोर के अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा सुना गया था, जिन्होंने 6 मार्च, 1943 को अपने आदेश से इसे खारिज कर दिया था और पहली संपत्ति की बिक्री की पुष्टि करने और डिक्री की पूर्ण संतुष्टि दर्ज करने का निर्देश दिया था। लगभग 12 दिनों के बाद, यानी 18 मार्च, 1943 को, पहली प्रत्यर्थी और दूसरी प्रत्यर्थी, जिन्हें 12 मार्च, 1936 को उनके पति की इच्छा के तहत गोद लिया गया था और बाद में अभिलेख पर लाया गया था, ने मद्रास अधिनियम की धारा 19 के तहत एक आवेदन दायर किया और उस अधिनियम के तहत कुछ राहत के लिए प्रार्थना की। यह आवेदन 22 मार्च, 1943 को खारिज कर दिया गया। इसके बाद, दो अपीलें दायर की गईं प्रत्यर्थियों की ओर से (जिन्हें इसके बाद कभी-कभी निर्णितऋणी के रूप में संदर्भित किया जाएगा), एक आदेश XXI, नियम 90 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत बिक्री को रद्द करने से इनकार करने वाले आदेश के खिलाफ, और दूसरा मद्रास एक्ट के तहत आवेदन खारीज करने के आदेश के खिलाफ़। इन अपीलों की सुनवाई मद्रास उच्च न्यायालय के दो विद्वान न्यायाधीशों द्वारा एक साथ की गई और उन्होंने यह विचार किया कि मद्रास अधिनियम के तहत निर्णितऋणीयों का आवेदन इस तथ्य के बावजूद कायम रखने योग्य था कि बिक्री की पुष्टि हो चुकी थी और डिक्री की पूर्ण संतुष्टि दर्ज की गई थी और निम्नलिखित प्रश्नों पर निष्कर्ष के लिए मामले को विचारण न्यायालय में भेज दिया, अर्थात्

(1) क्या आवेदक कृषक थे; और (2) यदि हां, तो 1938 के मद्रास अधिनियम IV के प्रावधानों को उनके विरुद्ध डिक्रेटल ऋण पर लागू करने का परिणाम क्या होगा?

जहां तक आदेश XXI, नियम 90 के तहत उनके आवेदन को खारिज करने के आदेश के खिलाफ निर्णितऋणीयों की अपील का संबंध है, विद्वान न्यायाधीश विचारण न्यायालय से सहमत थे कि बिक्री बरकरार रहनी चाहिए, लेकिन अपील पर अंतिम आदेश पारित करने से इनकार इस आधार पर कर दिया कि "यह 1938 के मद्रास अधिनियम IV की धारा 19 के तहत राहत के लिए निर्णितऋणीयों के संबंधित आवेदन पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।"

अधीनस्थ न्यायाधीश ने रिमांड पर उच्च न्यायालय द्वारा उनसे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार दिया:-

(1) निर्णितऋणी कृषक नहीं थे और इसलिए मद्रास अधिनियम के लाभों के हकदार नहीं थे और

(2) यदि वे कृषक थे, तो वे डिक्री के तहत कुछ भी भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं थे क्योंकि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, बिक्री की तारीख पर ऋण निर्वहित समझा गया।

हालाँकि, जब मामला उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों के सामने आया, तो उन्होंने विचारण न्यायालय के पहले निष्कर्ष को उलट

दिया और माना कि अधिनियम के अर्थ के तहत निर्णितऋणी कृषक थे, और धारा 8(2) के मद्देनजर ऋण का निर्वहन किया गया था। साथ ही, उन्होंने माना कि बिक्री रद्द करने योग्य नहीं है, और इस दृष्टिकोण से एक अपील को खारिज कर दिया और दूसरे को अनुमति दे दी। इसके बाद कुछ निम्नलिखित कार्यवाहियाँ हुईं जिनका उल्लेख करना अनावश्यक नहीं है, लेकिन इस तथ्य के लिए कि निर्णितऋणीयों ने इन अपीलों की पोषणीयता के लिए अपनी प्रारंभिक आपत्तियों में से एक के समर्थन में उन पर भरोसा करने का प्रयास किया है।

ऐसा प्रतीत होता है कि दो अपीलों में उच्च न्यायालय का फैसला सुनाए जाने के अगले दिन, प्रत्यर्थियों के वकील ने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को एक पत्र लिखकर दोनों मामलों को 'उल्लेखित करने के लिए' अपीलों में उनके द्वारा पारित आदेशों के परिणामस्वरूप आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त करने के लिए न्यायालय के समक्ष रखने का निर्देश दिया। इस पत्र को विद्वान न्यायाधीशों के समक्ष तब तक नहीं रखा गया जब तक कि निर्णय पर उनके हस्ताक्षर नहीं हो गए और तदनुसार निर्णितऋणीयों ने दो याचिकाएँ दायर कीं, एक उच्च न्यायालय में समीक्षा याचिका थी और दूसरी विचारण न्यायालय में प्रार्थना करते हुए एक याचिका थी कि डिक्रीधारक को याचिकाकर्ताओं को बिक्री की तारीख से भुगतान की तारीख तक 6 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज के साथ 21,000 रुपये की खरीद राशि का

भुगतान करने का आदेश दिया जा सकता है।" अधीनस्थ न्यायालय ने बाद की याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह सुनवाई योग्य नहीं है, और निर्णितऋणीयों ने आदेश के खिलाफ अपील दायर की। अपील के साथ-साथ निर्णितऋणीयों की समीक्षा याचिका पर विद्वान न्यायाधीशों द्वारा एक साथ सुनवाई की गई, जिन्होंने डिक्री-धारक के वकील को यह चुनने का निर्देश दिया कि क्या उसका पक्षकार खरीद का पैसा अदालत में जमा करेगा या बिक्री को रद्द करवाएगा। डिक्री-धारक ने एक संक्षिप्त स्थगन के लिए आवेदन किया और अंततः 15 नवंबर, 1946 को उसके वकील ने कहा कि उसका मुवक्किल उस संपत्ति को बरकरार रखना चाहता है जो उसने खरीदी थी और खरीद के पैसे का भुगतान अदालत में करना चाहता था। इसके बाद उन्हें उस तारीख से 3 महीने के भीतर 21,000 रुपये ब्याज सहित भुगतान करने का निर्देश दिया गया।

इसके बाद, अपीलकर्ता (डिक्री-धारक) ने उच्च न्यायालय से अपील करने की अनुमति प्राप्त करके हमारे सामने इन अपीलों को दायर किया। यहां यह कहा जा सकता है कि अपील की अनुमति के लिए आवेदन के साथ, अपीलकर्ता ने पूर्व आवेदन दाखिल करने में हुई देरी को माफ करने के लिए एक आवेदन दायर किया था, जिसे उन्होंने मुख्य रूप से उच्च न्यायालय में पिछली अपीलें के निर्णयों की समीक्षा के लिए कार्यवाही

का हवाला देकर बताया था। यह आवेदन स्वीकार कर लिया गया और विलंब माफ कर दिया गया।

जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, इन अपीलों में उठने वाला मुख्य बिंदु इस मुकदमे पर मद्रास अधिनियम के प्रभाव से संबंधित है। वह अधिनियम पारित किया गया और 1938 में लागू हुआ, जबकि निष्पादन की कार्यवाही अभी भी जारी थी। यह स्मरणीय होगा कि बिक्री 6 जुलाई, 1935 को हुई थी; और इसे रद्द करने के लिए आवेदन का निस्तारण 6 मार्च, 1943 तक नहीं किया गया था। लेकिन, अजीब बात है, इस अवधि के दौरान निर्णितऋणीयों ने मद्रास अधिनियम के तहत किसी भी राहत के लिए आवेदन नहीं किया था, और उन्होंने बिक्री की पुष्टि और डिक्री की संतुष्टि दर्ज होने के बाद ही अपना आवेदन किया था। यह विलंबित आवेदन अधिनियम के तहत निर्णितऋणीयों द्वारा दावा किए गए अधिकार को किस हद तक प्रभावित करता है, यह इन अपीलों में उठाए गए प्रश्नों में से एक है, और मैं अधिनियम के आवश्यक प्रावधानों और उच्च न्यायालय के निष्कर्षों, जिनसे कई विवादास्पद बिन्दु उत्पन्न हुए, का हवाला देने के बाद इसका निस्तारण करुंगा ।

अधिनियम की जो धाराएँ इन अपीलों के प्रयोजन के लिए महत्वपूर्ण हैं वे धारा 3, 8 और 19 हैं। धारा 3 एक कृषक को परिभाषित करती है और इसमें यह कहते हुए एक परंतुक है कि कुछ मामलों में किसी व्यक्ति

को कृषक नहीं माना जाएगा। इस परंतुक का प्रासंगिक खंड, जिसका उल्लेख मुझे बाद में भी करना होगा, खंड (घ) है जो इस प्रकार है:--

"बशर्ते किसी व्यक्ति को 'कृषक' नहीं माना जाएगा यदि वह-

(घ) मद्रास एस्टेट भूमि अधिनियम, 1908 के तहत एक संपत्ति का भूमिधारक है, या उसके किसी शेयर या हिस्से का, जिसके संबंध में संपत्ति, शेयर या हिस्से के संबंध में 500 रुपये से अधिक की कोई राशि है का भुगतान पेशकैश या 100 रुपये से अधिक की किसी भी राशि का भुगतान छोड़-किराया, जोड़ी, कट्टुबाड़ी, पोरुप्पु या इसी तरह के रूप में किया जाता है या मालाबार किरायेदारी अधिनियम, 1929 के तहत एक जन्मी है, जो 500 रुपये से अधिक की कोई भी राशि का भुगतान प्रांतीय सरकार को भूमि राजस्व के रूप में करता है।

इस प्रावधान के संदर्भ में सटीक प्रश्न जो उठता है वह यह है कि क्या टेडलाम गांव के मालिक होने के कारण, निर्णितऋणीयों को अधिनियम के तहत राहत का हकदार नहीं माना जाना चाहिए। अन्य अन्य मुख्य धाराए 8 और 19 इस प्रकार हैं:--

"8. 1 अक्टूबर 1932 से पहले लिए गए ऋणों को यहां उल्लिखित तरीके से परिकलित किया जाएगा, अर्थात्:-

(1) कृषक के किसी भी लेनदार के पक्ष में 1 अक्टूबर 1937 को बकाया सभी ब्याज, चाहे वह कानून, प्रथा या अनुबंध के तहत या

न्यायालय के डिक्री के तहत देय हो और क्या ऋण या अन्य दायित्व एक डिक्री में बदल गया है या नहीं, चुकाया हुआ माना जाएगा, और केवल मूलधन या उसका ऐसा हिस्सा जो बकाया हो उस तिथि पर, कृषक द्वारा चुकाई जाने वाली राशि माना जाएगा।

(2) जहां किसी कृषक ने किसी लेनदार को मूल राशि का दोगुना भुगतान किया है, चाहे मूलधन या ब्याज या दोनों के माध्यम से, मूलधन सहित ऐसा ऋण पूरी तरह से चुकाया हुआ माना जाएगा।

(3) जहां मूलधन या ब्याज या दोनों के माध्यम से चुकाई गई रकम मूलधन की राशि के दोगुने से कम हो, ऐसी राशि केवल इस कमी को पूरा करेगी, या मूल राशि या मूल राशि का ऐसा हिस्सा जो बकाया है, जो भी कम हो, चुकाया जाएगा।

(4) धारा 22 से 25 के प्रावधानों के अधीन, उप-धारा (1), (2) और (8) में शामिल किसी भी बात को लेनदार को भुगतान की गई किसी भी राशि को वापस करने की आवश्यकता नहीं माना जाएगा, या यह नहीं माना जाएगा कि देनदार को उस देय राशि से अधिक भुगतान करना होगा जो वास्तव मे उसे भुगतान करनी पडती यदि यह अधिनियम पारित नहीं हुआ होता।

स्पष्टीकरण.--जहां एक ऋण को उसी लेनदार के पक्ष में नवीनीकृत किया गया है या एक नए दस्तावेज़ में शामिल किया गया है, मूलधन को

मूल रूप से लेनदार द्वारा ऐसी रकम के साथ, यदि कोई हो, जो बाद में मूलधन के रूप में दिया गया हो, को अकेले ही कृषक द्वारा इस धारा के तहत चुकाई जाने वाली मूल राशि माना जाएगा।

19. जहां इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले, किसी न्यायालय ने किसी ऋण के पुनर्भुगतान के लिए डिक्री पारित की है, वह किसी भी ऋणी के आवेदन पर, जो कृषक है या हिंदू संयुक्त परिवार ऋण के संबंध में, परिवार के किसी भी सदस्य का आवेदन, चाहे वह निर्णय-ऋणी हो या नहीं या डिक्री धारक के आवेदन पर, इस अधिनियम के प्रावधानों को ऐसी डिक्री पर लागू करेगा और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में किसी भी बात के बावजूद भी लागू होगा व तदनुसार डिक्री में संशोधन करें या संतुष्टि दर्ज करें, जैसा भी मामला हो:

बशर्ते कि ऐसे किसी भी डिक्री के संबंध में किए गए सभी भुगतान या वसूल की गई रकम, चाहे इस अधिनियम के शुरू होने से पहले या बाद में, पहले लेनदार को मूल रूप से डिक्री के अनुसार सभी लागतों के भुगतान में लागू की जाएगी।

ये धाराएं महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वर्तमान मामले में निर्णितऋणीयों ने अधिनियम की धारा 19 के तहत डिक्री में संशोधन करने के लिए कहा और उन्हें धारा 8 के तहत राहत का हकदार माना गया ।

अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख करने के बाद, अब उच्च न्यायालय के मुख्य निष्कर्षों को बताना आवश्यक हो गया है, जिस पर इस अपील का निर्णय आएगा। ये निष्कर्ष हैं-

(1) कि टेडलाम गांव की बिक्री, जो 6 जुलाई, 1935 को हुई और 6 मार्च, 1943 को पुष्टि की गई, एक अच्छी बिक्री थी;

(2) कि इस बिक्री से टेडलाम गांव का हक डिक्री- धारक को दिया गया और अपील की सुनवाई में उच्च न्यायालय को इस आधार पर आगे बढ़ना उचित था कि टेडलाम गांव की बिक्री के बाद निर्णितऋणी इसके मालिक नहीं रह गए हैं, वे अधिनियम की धारा 3 के परंतुक के खंड (घ) से प्रभावित नहीं होंगे और

(3) बिक्री की तारीख पर डिक्री संतुष्ट हो गई थी और डिक्री धारक बेची गई संपत्ति की पूरी कीमत निर्णितऋणीयों को चुकाने के लिए उत्तरदायी था।

उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों के खिलाफ निर्देशित मुख्य तर्क हैं: सबसे पहले, वे आत्म-विरोधाभासी हैं, क्योंकि यदि बिक्री उस तारीख को प्रभावी बिक्री थी जिस दिन बिक्री आयोजित की गई या पुष्टि की गई थी, तो डिक्री भी उस तारीख को संतुष्ट थी और निर्णितऋणी अब मद्रास अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के हकदार नहीं थे; और दूसरी बात, उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों द्वारा लिया गया विचार

कि बिक्री को रद्द करने से इनकार करने वाले आदेश के खिलाफ अपील के बावजूद वे इस आधार पर आगे बढ़ सकते हैं कि निर्णितऋणी बिक्री की तारीख़ से टेडलाम गांव के मालिक नहीं रह गए हैं क़ानूनी तौर पर ग़लत थी।

इसमें सबसे पहले दूसरे बिंदु पर चर्चा होगी जिस पर मुझे गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। उच्च न्यायालय ने मेरी राय में इस आधार पर सही कदम उठाया है कि टेडलाम गांव का स्वामित्व निर्णितऋणीयों को अधिनियम की धारा 3 के प्रावधान के खंड (घ) के दायरे में लाएगा, और उन्हें इसके तहत किसी भी राहत से वंचित कर देगा। निर्णय-ऋणी की ओर से हमारे समक्ष इस दृष्टिकोण का दो आधारों पर विरोध किया गया था:---(1) कि निर्णय-ऋणी के पूर्वज के पक्ष में दिए गए अनुदान में पूरा इनाम गांव शामिल नहीं था और इसलिए जो कुछ उनके स्वामित्व में था, वह मद्रास संपदा भूमि अधिनियम (1908 का मद्रास अधिनियम) के तहत एक संपत्ति नहीं था।; (2) कि आवेदन की तिथि पर, निर्णय-ऋणकर्ता ग्राम टेडलाम के भूमिधारक नहीं थे क्योंकि गाँव 1 फरवरी, 1937 से एक रिसीवर के कब्जे में था, और रिसीवर उक्त तारीख पर भूमिधारक था। हालाँकि मुझे इनमें से किसी भी तर्क में कोई बल नज़र नहीं आता। पहले तर्क को प्रदर्श पी-1 द्वारा समर्थित करने की मांग की गई थी जो इनामों का एक रजिस्टर है और जो दर्शाता है कि 596 एकड़ की

सीमा तक पोरामबोक या बंजर भूमि को इनाम के क्षेत्र से काटा जाना था। हालाँकि इस मुद्दे को विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से निस्तारित किया गया है, जिन्होंने सही ही बताया है कि मद्रास संपदा भूमि (संशोधन) अधिनियम, 1945 [1945 का मद्रास अधिनियम संख्या II] के मद्देनजर इसमें कोई बल नहीं है। दूसरा बिंदु भी उतना ही अप्रासंगिक है, क्योंकि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि किसी संपत्ति का मालिक केवल इसलिए उसका मालिक नहीं रह जाता क्योंकि इसे रिसीवर के हाथों में सौंप दिया जाता है। सही स्थिति यह है कि रिसीवर वास्तविक मालिक का प्रतिनिधित्व करता है, चाहे वह कोई भी हो, और केवल रिसीवर की नियुक्ति से वास्तविक मालिक मद्रास एस्टेट भूमि अधिनियम के तहत भूमिधारक होना समाप्त नही होता है।

अब मैं मामले में महत्वपूर्ण प्रश्न पर वापस आऊंगा, अर्थात्, क्या उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने इस आधार पर अपील का न्यायोचित निर्णय लिया था कि निर्णय-ऋणी टेडलाम गांव के मालिक नहीं रह गए थे और उस हिसाब से वे मद्रास अधिनियम की धारा 3 के परंतुक के खंड (घ) से प्रभावित नहीं थे। इस स्तर पर, सिविल प्रक्रिया संहिता के कुछ प्रावधानों का उल्लेख करना उपयोगी होगा जो सीधे तौर पर इस सवाल पर निर्भर करते हैं कि किसी डिक्री के निष्पादन में बेची गई अचल संपत्ति का स्वामित्व क्रेता को कब दिया जाता है। प्रावधानों में से एक

आदेश XXI, नियम 92 है, जो प्रदान करता है कि "जहां नियम 89, नियम 90 या नियम 91 के तहत कोई आवेदन नहीं किया जाता है, या जहां ऐसा आवेदन किया जाता है और अस्वीकार कर दिया जाता है, अदालत बिक्री की पुष्टि करने वाला एक आदेश देगी, और उसके बाद बिक्री पूर्ण हो जाएगी।" दूसरा प्रासंगिक प्रावधान धारा 65 है जो इस प्रकार है:--

> "जहां अचल संपत्ति डिक्री के निष्पादन में बेची जाती है और ऐसी बिक्री पूर्ण हो गई है, संपत्ति उस समय से क्रेता में निहित मानी जाएगी जब संपत्ति बेची गई है, न कि उस समय से जब बिक्री पूर्ण हो गई है।"

भवानी कुँवर बनाम मथुर्न प्रसाद सिंह में यह प्रश्न कि जब एक बन्धकदार, जिसने डिक्री के निष्पादन में कुछ गाँव खरीदे हैं, उसके द्वारा खरीदी गई संपत्तियों पर सीधे अधिकार प्राप्त कर लिया, तो यह विचार के लिए उठा, और प्रिवी काउंसिल ने सही बताया कि "बंधक डिक्री के निष्पादन में बिक्री, बिक्री की वास्तविक तारीख से प्रभावी हुई, न कि इसकी पुष्टि से।" एक साधारण मामले में, ऊपर उद्धृत प्रावधानों से विवाद का निस्तारण हो जाना चाहिए, लेकिन, वर्तमान मामले में, आदेश XXI, नियम 90 के तहत बिक्री को रद्द करने से इनकार करने वाले आदेश के खिलाफ अपील के कारण मामला जटिल हो गया है। ऐसे मामले में, आमतौर पर कहें तो, सही स्थिति यह प्रतीत होती है कि जब तक अपीलीय

न्यायालय द्वारा मुकदमे का अंतिम निर्धारण नहीं हो जाता, तब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं होता है। इस सिद्धांत को कई मामलों में मान्यता दी गई है, लेकिन चंद्रमणि शाह बनाम अनर्जन बीबी का हवाला देना पर्याप्त होगा। उस मामले का शीर्षक इस प्रकार है:--

> "जहां एक अधीनस्थ न्यायाधीश ने निष्पादन में बिक्री को रद्द करने के लिए आदेश XXI, नियम 90 के तहत एक आवेदन को अस्वीकार कर दिया है, और बिक्री की पुष्टि करने वाले नियम 92 (1) के तहत एक आदेश दिया है, और अस्वीकृति की अपील उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई है, आदेश XXI, नियम 95 के तहत एक आवेदन के लिए भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1908, अनुसूची I, अनुच्छेद 180 द्वारा प्रदान की गई तीन वर्ष की अवधि, क्रेता द्वारा कब्जे की डिलीवरी के लिए अपील के आदेश की तारीख से मानी जाती है । सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायाधीश के समान शक्तियां प्राप्त हैं, अनुच्छेद 180 के प्रयोजन के लिए 'वह समय जब बिक्री पूर्ण हो जाती है' वह तब होता है जब उच्च न्यायालय अपील का निस्तारण करता है ।"

भारतीय परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 180 के तहत, परिसीमा की अवधि "उस तारीख से मानी जाती है जब बिक्री पूर्ण हो जाती है। "यदि हम इन शब्दों को एक संकीर्ण और शाब्दिक अर्थ देते हैं, तो परिसीमा की अवधि उस तारीख से मानी जानी चाहिए जब निष्पादन की मूल अदालत बिक्री की पुष्टि करती है। लेकिन, जैसा कि प्रिवी काउंसिल ने बताया था, अपीलीय न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय के पास अधीनस्थ न्यायालय के समान शक्तियां थीं और यह केवल तब होता है जब अपील उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी जाती है तब बिक्री की पुष्टि करने वाला अधीनस्थ न्यायालय का आदेश

पूर्ण बन जाता है। अपीलीय अदालत के फैसले तक, बिक्री की पुष्टि करने वाले आदेश पर कोई अंतिम मुहर नहीं लगाई गई थी।

यह स्पष्ट है कि इस मामले में डिक्री की संतुष्टि दर्ज करने वाले आदेश और बिक्री की पुष्टि करने वाले आदेश पर भी यही नियम लागू होगा। यदि डिक्री की संतुष्टि दर्ज करने वाला आदेश अंतिम नहीं था और अपील का निर्णय होने तक एक अपूर्ण आदेश बना रहा, तो बिक्री की पुष्टि करने वाले आदेश में वही अपूर्ण स्वरूप होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में प्रत्यर्थियों की ओर से दायर उनके मामले के बयान में इस स्थिति को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया है।

यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इस मामले में उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने असंगत रुख अपनाया है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, उन्होंने अपीलों में से एक को अनुमति देने के उद्देश्य से यह माना है कि निर्णय-देनदारों पर अधिनियम की धारा 3 के परंतुक के खंड (घ) का प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि वे 1935 में बिक्री की तारीख पर टेडलाम गांव के मालिक नहीं रहे। यदि यह निष्कर्ष सही है, तो इसे तर्क के रूप में पालन करना चाहिए कि बिक्री की तारीख पर डिक्री पूरी तरह से संतुष्ट थी, क्योंकि बिक्री के समयडिक्री के तहत देय राशि से अधिक राशि प्राप्त हुई थी और अतिरिक्त राशि डिक्री-धारक द्वारा न्यायालय में जमा की गई थी। बिक्री और संतुष्टि एक साथ चलनी चाहिए और यदि बिक्री को अंतिम रूप दिया जाना है तो इसे डिक्री की संतुष्टि को दर्ज करने वाले आदेश के साथ भी जोड़ा जाना चाहिए। मुझे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि यदि डिक्री का अस्तित्व समाप्त हो गया होता, तो मद्रास अधिनियम के तहत निर्णय-देनदारों द्वारा किसी राहत का दावा नहीं किया जा सकता था। दूसरी ओर, यदि अपील का निर्णय इस आधार पर किया जाना था कि डिक्री की संतुष्टि को दर्ज करने वाला आदेश अंतिम नहीं था, तो बिक्री के प्रभाव के संबंध में भी वही दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए था। यह भी स्पष्ट है कि यदि अधिनियम के प्रावधानों के लागू होने से बिक्री की तिथि पर डिक्री संतुष्ट हो जाती है, तो बिक्री टिक नहीं सकती है, क्योंकि जो डिक्री पहले ही संतुष्ट हो चुकी है, उसके निष्पादन में संपत्ति कैसे बेची जा सकती है। फिर भी, इस तथ्य के

बावजूद कि डिक्री के तहत कुछ भी देय नहीं था, उच्च न्यायालय ने माना है कि बिक्री एक अच्छी बिक्री थी और कायम रहेगी। मामले में सही दृष्टिकोण अपील के प्रयोजन के लिए यह मान लेना चाहिए था कि अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा पारित कोई भी आदेश अंतिम नहीं था। उस दृष्टिकोण से, उच्च न्यायालय में की गई अपीलों का निर्णय इस आधार पर नहीं किया जा सकता था कि निर्णय-देनदार टेडलाम संपत्ति के मालिक नहीं रह गए थे और इसलिए वे मद्रास अधिनियम की धारा 3 के परंतुक के खंड (घ) से प्रभावित नहीं हुए थे। मेरी राय में, उच्च न्यायालय के फैसले को कायम नहीं रखा जा सकता है, और अपील की अनुमति देनी होगी।

अब मैं प्रत्यर्थियों की ओर से उठाई गई दो प्रारंभिक आपत्तियों पर बहुत संक्षेप में विचार करूंगा। पहली आपत्ति यह है कि उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ परिषद में महामहिम के समक्ष अपील करने की अनुमति के लिए आवेदन परिसीमा अवधि के तहत वर्जित था, क्योंकि अपीलकर्ता द्वारा समर्थन में उच्च न्यायालय में दायर हलफनामे में बताए गए कारण देरी को माफ करने के लिए उसके आवेदन का परिसीमा अधिनियम के खंड 5 के अर्थ में पर्याप्त कारण नहीं बनता है। इस आपत्ति का उत्तर उन तथ्यों में मिलेगा जो पहले ही बताये जा चुके हैं। देरी मुख्य रूप से उच्च न्यायालय के आदेश की समीक्षा के कारण हुई और उच्च न्यायालय ने माना कि देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण थे। यह न्यायालय

उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग किए गए विवेक को खारिज नहीं कर सकता है और इन अपीलों में मामले को फिर से नहीं खोला जा सकता है। दूसरी आपत्ति इस तथ्य पर आधारित है कि डिक्री धारक को उच्च न्यायालय द्वारा यह चुनने का विकल्प दिया गया था कि वह खरीद का पैसा जमा करेगा या बिक्री को रद्द कर देगा, और उसके वकील ने 15 नवंबर 1946 को विद्वान न्यायाधीशों को बताया कि उनका मुवक्किल उस संपत्ति को अपने पास रखना चाहता था जो उसने खरीदी थी और खरीद के पैसे नकद में भुगतान करना चाहता था। यह तर्क दिया गया है कि इस कथन के मद्देनजर अपीलकर्ता के लिए यह तर्क देना संभव नहीं है कि उसे निर्णय-देनदारों को कोई राशि का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। यह आपत्ति भी पूरी तरह से किसी भी तथ्य से रहित है, क्योंकि यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के आदेश से बंधे होने के लिए सहमति व्यक्त की है और चुनाव के कारण इसके खिलाफ अपील करने का अपना अधिकार छोड़ दिया है।

प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया कि बिक्री को उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया जाना चाहिए था क्योंकि 16 फरवरी, 1934 को डिक्रीधारक को बोली लगाने और खरीद मूल्य के विरुद्ध डिक्रीटल राशि निर्धारित करने की अनुमति पहले की बिक्री तक ही सीमित थी और उस स्थिति तक विस्तारित नहीं हुई जो 16 मार्च, 1935 को बिक्री हुई थी, मूल

रूप से तय की गई अपसेट कीमत कम होने के बाद। व्यक्तिगत रूप से, मैं यह मानने को इच्छुक हूं कि अनुमति में विचाराधीन बिक्री शामिल थी, लेकिन बताए गए तथ्यों पर कायम रहना मुश्किल है कि ऐसी कोई महत्वपूर्ण अनियमितता थी जो बिक्री को प्रभावित करेगी। यहां जो सटीक तर्क दिया गया है, वह नीचे की अदालतों में दिया गया था, लेकिन उसे न तो अधीनस्थ न्यायाधीश और न ही उच्च न्यायालय का समर्थन मिला। इसके अलावा, प्रत्यर्थी इन अपीलों में इस मुद्दे को नहीं उठा सकते क्योंकि उन्होंने बिक्री को बरकरार रखने वाले उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की है।

इन परिस्थितियों में, मैं अपील की अनुमति दूंगा, उच्च न्यायालय के आदेशों को रद्द कर दूंगा और विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश के आदेश को बहाल करूंगा। हालाँकि इन अपीलों में लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

मुखर्जी जे.— मैं मेरे विद्वान भाई, फजल अली जे. द्वारा अभी दिए गए फैसले से सहमत हूं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है जिसे मैं उपयोगी रूप से जोड़ सकूं।

चन्द्रशेखर अय्यर जे.--जिन तथ्यों के कारण यह अपीले उत्पन्न है और निर्णय के लिए जो प्रश्न हैं, वे मेरे विद्वान भाई फजल अली जे. द्वारा अभी सुनाए गए फैसले में बताए गए हैं। मैं प्रत्यर्थियों के लिए उनके

विद्वान अधिवक्ता, श्री वी. रंगाचारी द्वारा उन्नत किए गए मुख्य तर्क पर केवल कुछ शब्द जोड़ना चाहता हूं।

यदि बिक्री की पुष्टि और डिक्री दर्ज किए जाने की संतुष्टि के कारण, गांव का स्वामित्व डिक्रीधारक को अनिश्चित काल के लिए पारित कर दिया गया था, तो अब कोई डिक्री या डिक्री ऋण कम नहीं किया जाना था। यदि, हालांकि, स्वामित्व पारित नहीं हुआ, क्योंकि यह अभी भी प्रत्यर्थियों के लिए आदेश XXI, नियम 90 के तहत अदालत की बिक्री को चुनौती करने के लिए विकल्प खुला था, वे गांव के भूमिधारक थे और, इस तरह, वे मद्रास कृषक राहत अधिनियम, 1938 की धारा 3 प्रावधान (घ) के दायरे में आएंगे, जो यह अधिनियमित करती है कि एक भूमिधारक जो गांव रखता है 100 रुपये से अधिक किराया छोड़ो या जोडी के रुप मे भुगतान करके, अधिनियम के अर्थ के अंतर्गत कृषक नहीं है।

उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण में स्पष्ट असंगतता को विद्वान वकील द्वारा मान्यता दी गई थी, स्वीकार नहीं किया गया था। एक दृष्टिकोण में, अब ऐसा कोई डिक्री नहीं है जिसके संबंध में कृषक राहत अधिनियम लागू हो सके और दूसरे दृष्टिकोण में, प्रत्यर्थी अधिनियम का लाभ नहीं उठा सकते थे, क्योंकि गाँव का स्वामित्व उन्हें वर्जित करता था। इस दुविधा का सामना करते हुए, श्री रंगाचारी ने कुछ अनोखा तर्क पेश किया। उन्होंने तर्क दिया कि यद्यपि बिक्री की पुष्टि पर स्वामित्व डिक्री-

धारक को पारित कर दिया गया और बिक्री की तारीख से उसमें निहित हो गया, प्रत्यर्थियों को अभी भी गांव में रुचि रखने वाला माना जा सकता है, क्योंकि बिक्री खुली थी या चुनौती के लिए उत्तरदायी थी और डिक्री-धारक का स्वामित्व अधूरा था। हालाँकि, इस स्थिति के लिए वास्तव में कोई समर्थन नहीं है। पुष्टि होने पर, डिक्री-धारक का स्वामित्व पूर्ण हो गया। यदि बिक्री को रद्द कर दिया गया था, तो स्वामित्व निर्णय-देनदार के पास वापस आ जाएगा। डिक्री-धारक में न्यायसंगत स्वामित्व जैसा कुछ नहीं है जिसे कुछ उद्देश्यों के लिए मान्यता दी जा सके और दूसरों के लिए मान्यता प्राप्त न हो।

मद्रास अधिनियम के तहत, "कृषक" का अर्थ है "एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास किसी कृषि या बागवानी भूमि में बिक्री योग्य हित है या जो किसी भूमिधारक के तहत किरायेदार, रैयत या उपक्रम-धारक के रूप में ऐसी भूमि में हित रखता है।" अधिनियम की धारा 10, उप-खंड (i) में प्रावधान है कि कृषक को ऋण कम करने का अधिकार किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगा, जो अधिनियम में परिभाषित "कृषक" होते हुए भी यदि दिनांक 1-10-1937 तक किसी भूमि का हित या पट्टा या उप-पट्टा धारण न हो, पर लागू नहीं होता है| 1935 में बिक्री के बाद, गांव में निर्णय-देनदारों का एकमात्र हित यह था कि सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत बिक्री को रद्द कर दिया जाए। यह हित धारा

3, उप-खंड (ii) (क) & (ख) द्वारा अपेक्षित हित नहीं है जो किरायेदार, रैयत या उपक्रम धारक के रूप में हित या बिक्री योग्य हित की बात करते हैं।

मैं अपने विद्वान भाई के निष्कर्ष से सहमत हूं।

अपील स्वीकृत

अपीलकर्ता के लिए प्रतिनिधि: एम.एस. कृष्णमूर्ति शास्त्री।

प्रत्यर्थियों के लिए प्रतिनिधि: एम.एस.के अयंगर।

चन्दन भाटी

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री चंदन भाटी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।